

प्रेषक,

डी0एस0 गर्बाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक / 9 मार्च, 2015

विषय: मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में नगरपालिका परिषद, नरेन्द्रनगर को सामुदायिक विकास भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 254/V-श0वि0-06-247(सा0)/05, दिनांक 06.02.2006 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगरपालिका परिषद, नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत सामुदायिक भवन निर्माण हेतु ₹70.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी, परन्तु कार्यदायी संस्था को ₹52.95 लाख की धनराशि ही प्राप्त हुयी। तत्क्रम में निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्र संख्या- 2471/श0वि0नि0/लेखा/बजट/2014-15, दिनांक 16.02.2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त निर्माण कार्य हेतु तत्समय कार्यदायी संस्था को मात्र ₹52.95 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी प्राप्त हुयी है।

2- उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरपालिका परिषद, नरेन्द्र नगर को मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में सामुदायिक विकास भवन निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अप्राप्त ₹17.65 लाख (रुपये सत्रह लाख पैंसठ हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- I. उक्त धनराशि ₹17.65 लाख (रुपये सत्रह लाख पैंसठ हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार सम्बन्धित कार्यदायी संस्था निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्र नगर बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- II. निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
- III. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
- IV. सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे।
- V. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
- VI. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
- VII. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।
- VIII. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।
- IX. इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- x. कार्य के मध्य तथा बाद में इसकी गुणवत्ता की चैकिंग किसी तृतीय तकनीकी पक्ष से कराके उसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जायेगी और इसका खर्च योजना की अनुमोदित लागत से ही वहन किया जायेगा।
- xi. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।
- xii. धनराशि का दिनांक 31-3-2015 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्यय के अनुदान सं०-13 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत- 191-स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05-नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"-20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेंट आई डी-s.1503130332 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी०एस० गर्बाल)
सचिव।

सं०-340 (1)/IV(2)-श०वि०-2015, तददिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, टिहरी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी०ओ० में इसे शामिल करें।
9. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, नरेन्द्र नगर।
13. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर।
14. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
उप सचिव।